



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062025-263602
CG-DL-E-04062025-263602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2393।

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947

No. 2393।

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2452(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकियां, प्रसुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और संस्कृति मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मंत्रालय कहा गया है) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और परिरक्षित करने के उद्देश्य से, उक्त स्कीमों के सामने विनिर्दिष्ट अपनी एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, अर्थातः-

- विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना (सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के माध्यम से);
- संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ या कनिष्ठ अध्येतावृति प्रदान करना (सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के माध्यम से);

(iii) सांस्कृतिक शोध कार्य के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृति (प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के माध्यम से); तथा

(iv) वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम (दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर के माध्यम से);

और वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभ कहा गया है) व्यक्तियों अर्थात् कलाकारों (अनुभवी कलाकारों सहित), शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक व्यवसायियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को उक्त स्कीमों और उनके संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत दी जाती है;

और उक्त स्कीमों के लिए व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

और जबकि उक्त मंत्रालय चाहता है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ, यह अपेक्षा करे कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण कराए, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे, या ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. (1) उक्त स्कीम के अंतर्गत उक्त लाभ चाहने वाले व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना अपेक्षित होगा अथवा आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा;
(2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से किया जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त मंत्रालय अपनी एजेंसियों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी नामांकन होना है, या रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करने या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा:

परंतु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं दी जाती है, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, या यदि उक्त मंत्रालय द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसे दस्तावेजों की तैयारी या रखरखाव से संबंधित प्राधिकारियों के डाटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को साक्षित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ऐसे प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थात्:-
अठारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक के लिए, जिसे आधार संख्या नहीं दी गई है:

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर प्रचालक द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आईडी होती है; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक यह साक्षित करने के लिए कि लाभार्थी अठारह वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थात् :—

- (i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से निकाला गया है; या
- (ii) भारतीय पासपोर्ट; या
- (iii) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण; या
- (iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि से संघर्षरत किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए

गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(v) विदेशी नागरिक के संबंध में,—

- (I) यदि वह भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक है, तो भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड;
- (II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
- (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है और उसके पास नेपाल या भूटान का पासपोर्ट है;
- (IV) यदि वह भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न व्यक्ति है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; और

(ग) लाभार्थी का फोटो युक्त निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जो उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को साक्षित प्रमाणित करता हो, अर्थात्:—

(i) राशन कार्ड;

(ii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार की रैंक से नीचे का न हो;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण ;

(vi) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि से संघर्षरत किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(vii) विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक है तो भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है और उसके पास नेपाल या भूटान का पासपोर्ट है;

(IV) यदि वह भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न व्यक्ति है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(viii) लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999

(1999 का 44) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि उक्त मंत्रालय विनिर्दिष्ट करे;

अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है:

(क) नामांकन की प्रक्रिया कराए गए लाभार्थी की पावती, जो नामांकन केंद्र पर प्रचालक द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आईडी होती है; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात्: —

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निवाचिक फोटो पहचान पत्र; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, और तहसीलदार की रैंक से नीचे का न हो; या

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या कार्यरत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र; या

(v) भारतीय पासपोर्ट; या

(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10 वीं कक्षा या 12 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण; या

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज; या

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र; या

(ix) भारत में प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि से संघर्षरत किसी बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारतीय विदेशी नागरिक कार्डधारक है, भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है और उसके पास नेपाल या भूटान का पासपोर्ट है;

(IV) यदि वह भारतीय विदेशी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न व्यक्ति है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

(xii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज़ है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय अधिनियम, 1999 (1999 का 44) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज जिसे उक्त मंत्रालय विनिर्दिष्ट करे;

(4) उक्त मंत्रालय द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से इस निमित्त नामोदिष्ट कोई अधिकारी खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को साक्षित करने वाली सूचना के संबंध में निम्नलिखित जांच करेगा,—

(क) नामांकन आईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं किया गया है, इसकी पुष्टि करने के लिए मायाधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर नामांकन आईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की जांच करना; तथा

(ख) अन्य दस्तावेज, इस प्रयोजन के लिए, किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता लेना तथा प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा करना, जो ऐसे दस्तावेजों में अंतर्विष्ट जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, उक्त मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लाभार्थियों को उक्त स्कीमों के अंतर्गत आधार संख्या की अपेक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. जहां किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण तरीके (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, वह किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमीट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थातः -

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमीट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या एक बार पिन आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक-आधारित या एक बार पिन आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त स्कीमों के अंतर्गत लाभ, यथास्थिति, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया कोड या आधार कागजविहीन ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसकी आधार संख्या सूजित होने पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात् आधार पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके एमआधार एप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है) शामिल है, जिसकी प्रमाणिकता आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार एप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए ऑफलाइन सत्यापन होने के बाद स्थापित की जाती है; तथा

(ii) आधार कागज विहीन आफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार एप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), जिसकी

प्रमाणिकता भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए व्यौरों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के बाद होती है।

4. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किन्हीं भी उक्त स्कीमों के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ से किसी बालक को वंचित नहीं किया जाएगा,—

(i) प्रक्रियाधीन प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में असफल रहने या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में; या

(ii) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के मामले में, जहां उसे आधार संख्या नहीं दी गई है;

(ख) उक्त स्कीमों में से किसी के अंतर्गत लाभ ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और उसके मातापिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति से दिया जाएगा; तथा

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसके संबंध में एक अभिलेख रखा जाएगा, जिसकी मंत्रालय द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर पुनर्विलोकन और लेखा-परीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त स्कीमों के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, उक्त मंत्रालय अपनी एजेंसियों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbt Bharat.gov.in> पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद संचालन तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एआरआईटी-15/3/2024-24]

गुरमीत सिंह चावला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2452(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Central Government in the Ministry of Culture (hereinafter referred to as the said Ministry) is administering the following schemes (hereinafter referred to as the said schemes) through its agencies specified against the said schemes, with the objective of promoting and preserving art and culture, namely:-

- (i) Award of Scholarships to Young Artists in Different Cultural Fields (through the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi);
- (ii) Award of Senior or Junior Fellowship to Outstanding Persons in the Fields of Culture (through the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi);
- (iii) Tagore National Fellowship for Cultural Research (through the Prime Ministers' Museum and Library, New Delhi); and
- (iv) Scheme for Financial Assistance for Veteran Artists (through the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur);

And whereas financial assistance (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the individuals namely, Artists (including Veteran Artists), researchers and cultural practitioners (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said schemes and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas expenditure for the said schemes are incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas the said Ministry is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said schemes shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number;

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian;

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Ministry through its agencies shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Ministry through its agencies for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below eighteen years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and

(b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below eighteen years of age, namely:—

(i) certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary; or

(ii) Indian passport; or

(iii) certificate or statement of marks of 10th class or 12th class, issued by a recognised board of school education; or

(iv) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(v) in respect of a foreign national,—

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, having passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; and

(c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—

(i) ration card;

- (ii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (iii) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (iv) Indian passport;
- (v) certificate or statement of marks of 10th class or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vi) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (vii) in respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, having passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (viii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) and the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (ix) Any other document as the said Ministry may specify;

For beneficiaries aged eighteen years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and
- (b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India; or
 - (ii) ration card; or
 - (iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar; or
 - (iv) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member; or
 - (v) Indian passport; or
 - (vi) certificate or statement of marks of 10th class or 12th class, issued by a recognised board of school education; or
 - (vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise; or
 - (viii) disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India; or
 - (ix) driving licence issued by authority in India; or
 - (x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act,

2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(xi) in respect of a foreign national,—

- (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
- (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
- (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, having passport of Nepal or Bhutan;
- (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) and the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii) any other document as the said Ministry may specify;

(4) An officer designated by the said Ministry through its agencies in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID on my Aadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Enrolment ID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
- (b) the other documents, for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the said Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said schemes.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

- (a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
- (b) in cases where biometric-based or one-time pin based modes of authentication are not possible, benefits under the said schemes may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of **Unique Identification Authority of India** on the Aadhaar Secure Quick Response Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - (i) an Aadhaar Secure Quick Response Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of **Unique Identification Authority of India** or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps; and
 - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of **Unique Identification Authority of India** or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of **Unique Identification Authority of India** on the document through the application developed by the Ministry or Department or schemes implementing agencies concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of **Unique Identification Authority of India**.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

- (a) benefit under any of the said schemes shall not be denied to a child,—
 - (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
 - (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number;
- (b) benefit under any of the said schemes shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
- (c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry through its agencies.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged eighteen years or more are not deprived of the benefit due to them under the said schemes, the said Ministry through its agencies shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. ARIT-15/3/2024-24]

GURMEET SINGH CHAWLA, Jt. Secy.